>

Title: Need to address the problems of women working as cooks under mid-day meal scheme in schools in Uttar Pradesh.

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): देश में मिड-डे-मिल योजना संचालित है, इस योजना में सभी प्राथमिक विद्यालयों में रसोइयों की नियुक्ति की गयी है । यह रसोइयां भोजन को कैसे गुणवत्ता युक्त बनाए, जब खाद्य सामग्री गुणवत्ता युक्त नहीं आ पाती । अगर यह सड़े-गले सामग्री का विरोध करें तो देश में आए दिन इस योजना से बीमार पड़ने व मरने वाले बच्चों को बचाया जा सकता है । परन्तु अगर यह विरोध कर दे तो इनको कार्य पर लगाने वालों की भृकुटी तन जाती है और इनको काम से निकाल दिया जाता है । इसलिए यह सड़े-गले सामान बनाने को मजबूर है । यहीं नहीं उत्तर प्रदेश में तो एक शासनादेश लागू कर दिया गया है कि जिस रसोइया का बच्चा उस स्कूल में पढ़ेगा वहीं भोजन बनाएगी । अब आप ही बताएं जब योजना प्रारंभ हुई तो स्कूलों पर रसोइयों की नियुक्ति की गयी । जिसमें 25 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाएँ व विधवाएँ थीं । वर्षों तक इनसे कार्य कराने के बाद इनको इसलिए हटाया जा रहा है कि इनके बच्चे स्कूल में नहीं है । इनके वेतन का कोइ शासनादेश नहीं मिलता है । मेरी केन्द्र सरकार से गुजारिश है कि मिड-डे-मिल योजना को व्यवस्थित कर इनमें भोजन बनाने वाली महिलाओं की समस्याओं का निदान करें एवं इनकों खराब भोजन हेतु जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है ।